

# अशोक गहलोत से पीछा छुड़ाना चाहता है कांग्रेस आलाकमान : घनश्याम तिवाड़ी

राज्यसभा सांसद तिवाड़ी ने कहा कि "गहलोत के कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना था, वह तो इस मुद्दे पर कुछ ना ही बोलें तो ठीक है। उनके मंत्री से लेकर अधिकारी तक जेल की सलाखों के पीछे गए हैं।"

**-कार्यालय संवाददाता-**  
जयपुर। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि "पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कांग्रेस का आलाकमान पीछा छुड़ाना चाहता है। क्योंकि राजस्थान की जनता से 3 बार उनकी सरकार को हिलाया है। गहलोत के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना था। पेपरलीक से लेकर जल जीवन मिशन के घोटालों की गुंज पूरे प्रदेश के साथ-साथ देशभर में है। जे.जे.एम. घोटाले में कांग्रेस के मंत्री से लेकर अधिकारी तक जेल की सलाखों के पीछे हैं।"



सांसद घनश्याम तिवाड़ी

**■ तिवाड़ी ने कहा कि "प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं का खाका अशोक गहलोत ने बिगाड़ा था, अब भजनलाल सरकार ओ.बी.सी. वर्ग को चुनाव में उसका अधिकार देगी।"**

गहलोत इंतजार शास्त्र की बात तो कर रहे हैं, परंतु सरकार तो तब हिल रही थी, जब उनके उपमुख्यमंत्री अपने विधायकों को लेकर चले गए थे। मल्लिकार्जुन खडगे जब आए थे और विधायकों को मीटिंग बुलाई गई थी, तब भी सरकार हिली थी। राजस्थान

की जनता ने तीन बार अशोक गहलोत की सरकार को हिलाया है। इसीलिए अब कांग्रेस का आलाकमान भी उनसे पीछा छुड़ाना चाहता चाहता है। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि अशोक गहलोत ने आरजीएचएस को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में भुगतान न होने की वजह से इस योजना की सेवाएं बार-बार बाधित होती थी।

इनकी गलतियों को ठीक करके आरजीएचएस योजना को अच्छे से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध रूप से सवा लाख से ज्यादा नोकियां दी है और भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। वह किस मुँह से बात कर रहे हैं, जबकि उनके कार्यकाल में पेपरलीक हुए थे। घनश्याम तिवाड़ी ने रिफाइनरी को लेकर कहा कि यह दुखद घटना

है, इसकी जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत अपने गिरेबां में झांक कर देखें। पंचायतीराज का खाका इन्होंने ही बिगाड़ा था। अब सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार इस वर्ग को चुनाव में आरक्षण के अधिकार का लाभ देना चाहती है। क्या अशोक गहलोत यह चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायतीराज चुनाव करा लिए जाएं। तिवाड़ी ने कहा कि जितना भ्रष्टाचार अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुआ उसे आज भी जनता याद करती है। जेजेएम घोटाले की चर्चा हर कोई करता है। इनकी डाली हुई पाईप लाइनों से पानी नहीं हवा निकलती है। अशोक गहलोत अपनी वरिष्ठता के अनुसार ही बयानबाजी करें और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने आलाकमान से बातचीत करें।

# प्रदेश के हर जिले में स्थापित होंगे 'मेंटल हैल्थ केयर सेल'

जयपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार होगा 'सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन मेंटल हैल्थ'

**■ टेली-मानस के जरिए अब तक 71 हजार से अधिक प्रदेशवासियों को मिला परामर्श**

जयपुर। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर शुरू किए गए "राज-ममता" (राजस्थान मेंटल अवेयरनेस, मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फोर शॉल्ड) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा नेशनल टेली मेंटल हैल्थ प्रोग्राम 'टेली मानस' का भी प्रदेशभर में प्रभावी संचालन किया जा रहा है।

भजनलाल सरकार की इस पहल से राजस्थान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश के एक 'मॉडल राज्य' के रूप में उभरने की ओर कदम बढ़ाएंगे। जयपुर में 'सेंटर ऑफ एक्सिलेंस इन मेंटल हैल्थ' की स्थापना की जा रही है। यहां अत्याधुनिक काउंसलिंग और

टेली-मेंडिसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों को भी विशेषज्ञों की सलाह मिल सकेगी। साथ ही, प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 'मेंटल हैल्थ केयर सेल' स्थापित किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को अपने ही जिले में विशेषज्ञ परामर्श, पुनर्वास और उपचार सुलभ हो सके। मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहे लोगों को तुरंत सहायता के लिए

संचालित 'टेली-मानस' (14416 और 18008914416) कार्यक्रम राजस्थान में अत्यंत सफल साबित हो रहा है। अब तक प्रदेश में कुल 71 हजार से अधिक लोगों ने इन टोल-फ्री नंबरों के जरिए परामर्श लिया है। 'राज-ममता' कार्यक्रम के तहत युवाओं में बढ़ते तनाव और आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मित्रों और आशा सहयोगियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि प्रारंभिक स्तर पर ही मानसिक रोगों के लक्षणों की पहचान कर त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

# योग और आयुर्वेद से मधुमेह नियंत्रण पर लगी विज्ञान की मुहर : आचार्य बालकृष्ण

टाइप-वन डायबिटीज को लेकर प्रख्यात हैल्थकेयर में पतंजलि का शोध प्रकाशित, 612 शोधपत्रों का किया अध्ययन



आचार्य बालकृष्ण

हरिद्वार। डायबिटीज के इलाज को लेकर पतंजलि के वैज्ञानिकों की ओर से किए गए शोध ने एक क्रांति को जन्म दिया है। जो वैश्विक स्तर पर लंबे समय से टाइप-1 डायबिटीज के मुख्य उपचार इंसुलिन थेरेपी को लेकर नजरिया बदलने को मजबूर कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान फ्रंटियर्स इन क्लिनिकल डायबिटीज एंड हेल्थकेयर शोध ने यह प्रमाणित किया है कि केवल इंसुलिन से नहीं बल्कि समग्र इलाज से ही मधुमेह को मात दी जा सकती है। जिसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, संतुलित आहार, जीवनशैली में सुधार तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना होगा। इसी अप्रैल माह में शोध को प्रकाशित किया गया है।

शोध में यह भी साबित किया है कि योग-प्राणायाम आदि को अपनाने से मरीजों के शुगर नियंत्रण, तनाव स्तर और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार देखा गया। शोध अध्ययन में लगभग 612 शोध पत्रों का विश्लेषण किया गया। इस शोध को पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने लीड किया है। इस शोध ने यह भी प्रमाणित किया है कि पतंजलि वेलनेस का वह मॉडल है, जिससे करोड़ों मरीज पहले से लाभ उठा रहे हैं और अब विज्ञान भी इसे सार्थक बता रहा है।

**■ आचार्य बालकृष्ण ने इस शोध को लीड करते हुए कहा "इंटीग्रेटेड थेरेपी वरदान है"**  
आयुर्वेद और नेचरोपैथी जैसी इंटीग्रेटेड थेरेपी मरीजों के लिए बेहद मददगार है। पतंजलि के वैज्ञानिकों ने इस ओर बड़ा पुरस्कार दिया है। इतना ही नहीं एकीकृत इलाज से स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर दिखा है। अब दुनिया भर में इस विषय पर शोध तेजी से बढ़ रही है और भारत ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। पतंजलि योग, आयुर्वेद और नेचरोपैथी के जरिये मधुमेह सहित कई जटिल और असाध्य रोगों को लगातार अपने वैज्ञानिक और साध्य आधारित प्रमाणों के साथ शोध कर रहा है। यहां यह गौर करने वाली बात है कि पतंजलि वेलनेस का वह मॉडल है जिससे करोड़ों मरीज पहले से लाभ उठा रहे हैं और अब विज्ञान भी इसे सही साबित कर रहा है। यह कोई वैकल्पिक इलाज नहीं है। यह आधुनिक और समग्र स्वास्थ्य सेवा की नई दिशा है। डायबिटीज का असली इलाज एकीकृत है और अब इस शोध के साथ इसके सबूत भी मौजूद हैं।

# हाईवे पर तलवारें लहराकर हुडदंग करने वाले सात बदमाश गिरफ्तार

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर गलता गेट इलाके में रविवार रात की घटना

**-कार्यालय संवाददाता-**  
जयपुर। राजधानी में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर बाइक सवार युवाओं द्वारा तलवारें लहराकर दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। गलता गेट थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य फरार साथियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में 20 से अधिक बाइकों पर सवार 40-50 युवक काफिले के रूप में हाईवे पर हुडदंग करते

नजर आए। यह घटना रविवार रात करीब 10:15 बजे की बताई जा रही है। वीडियो में युवक ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अवहेलना करते हुए लहराते हुए बाइक चला रहे थे और चलते बाइकों पर तलवारें लहराकर राहगीरों में दहशत फैला रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए गलता गेट थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और दबिश देकर सात युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में फरहान (24) निवासी ठाठर कॉलोनी आमेर, असगर

अली (33) निवासी प्रभात कॉलोनी गलता गेट, मोहम्मद अजीम (32) निवासी रहीम कॉलोनी, अजरुद्दीन उर्फ अज्जु (28) निवासी ईदगाह कच्ची बस्ती, सलीम कुरैसी (35) निवासी गुलवार कॉलोनी पाडामंडी, तौफिक खान (26) निवासी एमडी रोड लालकोट और जिशान खान (20) निवासी सैयद कॉलोनी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हुडदंग और दहशत फैलाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। अन्य फरार आरोपियों को तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।

# ट्रांसजेंडर संशोधन कानून के कुछ प्रावधानों को क्यों ना कर दें रह?

राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव और केन्द्रीय विधि सचिव को नोटिस जारी कर पूछा

जयपुर (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव और केन्द्रीय विधि सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2026 के कुछ प्रावधान इस समुदाय के हितों के विपरीत होने के कारण क्यों ना उनको रद्द कर दिया जाए। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश नई भौम संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर

सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता मितुल जैन ने अदालत को बताया कि केन्द्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2019 में कुछ प्रावधानों में बदलाव कर इस साल संशोधन अधिनियम लागू किया है। इस संशोधन अधिनियम के कई प्रावधान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के केस में व्यवस्था दी थी कि ट्रांसजेंडर अपने

आप को ट्रांसमैन या ट्रांसवुमन मान सकता है। वहीं पुराने कानून में भी इसी तरह की व्यवस्था थी। याचिका में कहा गया कि संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि अब संबंधित जिले का सीएमएचओ की अध्यक्षता वाला मेडिकल बोर्ड ट्रांसजेंडर व्यक्ति की मेडिकल जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट स्थानीय मजिस्ट्रेट को देगा। वहीं मजिस्ट्रेट ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करेगा। ऐसे में इस प्रावधान से ट्रांसजेंडर व्यक्ति के स्वकल्पित लिंग पहचान के अधिकार को समाप्त हो गया

है और वह प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी पहचान मानने के लिए बाध्य है। इसी तरह इस कार्रवाई से उनकी पहचान उजागर होगी, जो निजता के अधिकार के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया कि संशोधन अधिनियम उन व्यक्तियों को भी बाहर कर देता है, जिन्होंने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करा ली है या हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं। ऐसे में संशोधन अधिनियम से इन्हें प्रावधानों को हटाया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

# मृतक सफाईकर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता

जयपुर। सीवर चैंबर की सफाई के दौरान 17 अप्रैल को जहरीली गैस से हुई दो स्वच्छता कर्मियों की मौत के मामले में मंगलवार को जयपुर नगर निगम ने पीडित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। नगर निगम स्वास्थ्य शाखा के उपयुक्त ओम थानवी पीडितों के निवास पहुंचे और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, वाल्मीकि समाज सरपंच मनोज चांवरिया व सफाई कर्मचारियों संगठनों के पदाधिकारियों को मौजूदगी में परिजनों को चेक सीपी प्रतिनिधिमंडल के चांदमारी (पुरानी बस्ती, शास्त्री नगर) निवासी अजय उर्फ सेठी और चिकारा कैंटीन क्षेत्र (नाला पावर हाउस) निवासी रामबाबू के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदन व्यक्त की। निगम की ओर से अजय की माता छोटी देवी और रामबाबू की पत्नी पुनम को मुआवजा राशि के चेक दिए गए।

# कांग्रेस ने सुनियोजित षडयंत्र से महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम को पारित होने से रोका

उन्होंने कहा कि "महिलाओं की भागीदारी के बिना देश के विकास और परिपक्व राजनीति की कल्पना संभव नहीं।"

जयपुर (कास)। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक का विपक्ष द्वारा विरोध करने को लेकर मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में महिलाओं ने सदैव परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और राजनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, हाडी रानी, रानी कर्णावती, रानी पद्मावती, पन्ना धाय तथा अमृता देवी बिर्नोई का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं का योगदान ऐतिहासिक रूप से प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद जब नरेंद्र मोदी महिलाओं को आरक्षण को एक सैद्धांतिक विषय मानती हैं और वह विश्वास रखती हैं कि महिलाओं की भागीदारी के बिना देश के विकास और



**■ वसुंधरा राजे महिला सशक्तिकरण की जीवंत प्रतीक : डॉ. अग्रवाल**

परिपक्व राजनीति की कल्पना संभव नहीं है। पार्टी जल्द से जल्द महिला आरक्षण को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भाजपा विरोधी दलों के इस रुख को महिला विरोधी बताते हुए उसकी निंदा की। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2023 में विपक्ष ने मजबूरी में मन मसोसकर इस विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन अब जब चुनाव दूर हैं, तो उन्हें लगता है कि जनता की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसी कारण वे दक्षिण भारत की सीटों में कमी जैसे विभिन्न बहानों के आधार पर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

# 'स्कूलों में लगे खेल उपकरणों की जांच करें खेल सचिव'

राज्य मानवाधिकार आयोग ने उदयपुर की निजी स्कूल में हैंडबॉल का पोत गिरने से छात्र की मौत पर प्रसन्नान लिया

**-कार्यालय संवाददाता-**  
जयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने उदयपुर के निजी स्कूल में हैंडबॉल के पोत गिरने से छात्र की दर्दनाक मौत को लेकर स्वर्णपत्रा से प्रसन्नान लिया है। इसके साथ ही आयोग ने खेल सचिव को कहा है कि वे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी स्कूलों को परिपत्र जारी करें। इसके साथ ही छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में लगे खेल उपकरणों आदि की जांच करें, जिससे अनाध छात्र खेलने के भ्रम में अपनी जान ना गंवाएं। अदालत ने अपेक्षा की है कि खेल सचिव सभी जिला मजिस्ट्रेट को इसके लिए पाबंद करेंगे।

वहीं आयोग ने मामले में उदयपुर कलेक्टर, शिक्षा निदेशक, एस्पी और संभागीय आयुक्त को कहा है कि वे सभी स्कूलों की सुरक्षात्मक जांच करते हुए छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और घटना का संपूर्ण ब्यौरा व तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें। आयोग ने पीडित परिवार को उचित मुआवजा देकर इसकी जानकारी भी पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि बीते सोमवार को आठ साल का बच्चा निजी स्कूल में हैंडबॉल के पोत पर खेल रहा था। इस दौरान पोत गिरने से वह गंभीर घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई थी।

# मोबाइल स्नैचर चढा पुलिस के हत्थे

जयपुर। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत दो अलग-अलग कार्रवाइयों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोबाइल स्नैचर और चोरी की वारदातों में शामिल तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिल, पांच मोबाइल फोन और घरेलू सामान बरामद किया है। पुलिस उपयुक्त (उत्तर) करण शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में बड़ती मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं के मद्देनजर गठित विशेष टीम ने 16 अप्रैल को हुई वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए भट्टा बस्ती निवासी साहिद चौहान (21) को गिरफ्तार किया। आरोपी राहगीरों से मोबाइल छीनकर फरार हो जाता था। पूछताछ में उसने मौज-मस्ती के लिए वारदात करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर दो बाइक और पांच मोबाइल बरामद किए गए। वहीं दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने निर्माणधीन मकान के स्टोर रूम से घरेलू सामान चोरी करने के मामले का

# रिफाइनरी में मरम्मत कार्य पूरा होते ही जल्द शुरू होगा कमर्शियल उत्पादन : मंत्री जोगाराम पटेल

संसदीय कार्य मंत्री ने बालोतरा में प्रैस वार्ता कर इस मुद्दे पर चर्चा की

बालोतरा/जोधपुर (कास)। राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को आयोजित प्रैस वार्ता में रिफाइनरी से जुड़ी अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना था, जिसे तकनीकी कारणों के चलते टालना पड़ा।



मंत्री पटेल ने बताया कि दोपहर करीब 1:55 बजे रिफाइनरी परिसर में लीकेज की समस्या सामने आई थी। घटना की जानकारी मिलते ही तकनीकी अधिकारियों और एचपीसीएल की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज एक घंटे के भीतर, लगभग 2:45 बजे तक स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। अधिकारियों की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया से एक संभावित बड़ी दुर्घटना को टाल दिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं आज रिफाइनरी पहुंचे और अंदर जाकर तकनीकी व्यवस्थाओं व बाहरी सुरक्षा इंतजामों का गहन निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कंट्रोल रूम में तैनात अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों से संवाद

# चारधाम यात्रा से पहले एडवाइजरी जारी

**-कार्यालय संवाददाता-**  
जयपुर। राजस्थान से चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बदलते मौसम और कम ऑक्सीजन स्तर को देखते हुए यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशक (जन स्वास्थ्य) डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड, कम हवा का दबाव, कम ऑक्सीजन, तेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और कम आर्द्रता के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो

सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा से पहले और दौरान सावधानी बरतना जरूरी है। विभाग ने एडवाइजरी में कहा है कि कम से कम 7 दिन की यात्रा योजना बनाएं, हर 1-2 घंटे में 5-10 मिनट का विश्राम लें, रोजाना 20-30 मिनट टहलें और श्वास व्यायाम करें, मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करें, जरूरी सामान साथ रखें। यात्रियों को गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और जरूरी दवाइयां साथ रखने की सलाह दी गई है। हृदय रोग, अस्थमा, हाई बीपी या मधुमेह से पीड़ित लोगों को यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच करवाने और

डॉक्टर की सलाह लेने को कहा गया है। यात्रा के दौरान शराब, कैफीनयुक्त पेय, धूम्रपान, नौद की गोलियां और तेज दर्द निवारक दवाओं से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही रोजाना कम से कम 2 लीटर तरल पदार्थ लेने और पौष्टिक आहार लेने की बात कही गई है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर 104 जारी किया गया है। सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, उल्टी, कमजोरी या चलने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या हेलपलाइन से संपर्क करें।

मंत्री पटेल ने बताया कि दोपहर करीब 1:55 बजे रिफाइनरी परिसर में लीकेज की समस्या सामने आई थी। घटना की जानकारी मिलते ही तकनीकी अधिकारियों और एचपीसीएल की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज एक घंटे के भीतर, लगभग 2:45 बजे तक स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। अधिकारियों की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया से एक संभावित बड़ी दुर्घटना को टाल दिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं आज रिफाइनरी पहुंचे और अंदर जाकर तकनीकी व्यवस्थाओं व बाहरी सुरक्षा इंतजामों का गहन निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कंट्रोल रूम में तैनात अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों से संवाद

कर उनकी कार्यक्षमता की सराहना की। साथ ही, आगत स्थिति में मुस्तैदी से काम करने वाली महिला अधिकारियों के साहस और समर्पण को भी विशेष प्रशंसा की।

मंत्री पटेल ने बताया कि रिफाइनरी एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है और लीकेज से हुआ नुकसान केवल एक सीमित हिस्से तक ही सीमित रहा। उन्होंने कहा कि लीकेज के वास्तविक कारणों की गहन जांच के लिए अन्य रिफाइनरियों से

विशेषज्ञों और बड़ी तकनीकी टीमों को बुलाया जा रहा है, ताकि समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मरम्मत कार्य पूरा होते ही रिफाइनरी अपने निर्धारित कार्यक्षमता के अनुसार कमर्शियल उत्पादन शुरू करेगी। साथ ही प्रशासन और तकनीकी टीमों लगातार निगरानी बनाए हुए है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह रिफाइनरी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मौलिक पाथर साबित होगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी।